गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 188
दि. 09.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

किडनी रोग के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर, 13.8 करोड़ लोग पीड़ित—चीन पहले स्थान पर, विशेषज्ञों ने दी गंभीर चेतावनी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में किडनी रोग एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहा है। वर्ष 2023 में भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया जहां सबसे अधिक लोग किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया वैश्विक अध्ययन के अनुसार, देश में लगभग 13.8 करोड़ लोग इस गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं। पहले स्थान पर चीन है, जहां 15.2 करोड़ लोग किडनी रोग से पीड़ित बताए गए हैं।

यह अध्ययन अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME), यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और ब्रिटेन के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर समय पर रोकथाम, शुरुआती जांच और समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो आने वाले वर्षों में किडनी रोग पूरी दुनिया के लिए महामारी जैसे खतरे का रूप ले सकता है।

अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2023 में किडनी रोग वैश्विक स्तर पर मौत का नौवां सबसे बड़ा कारण बना। इस बीमारी की वजह से करीब 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व में इसके मामलों की दर सबसे अधिक 18% रही, जबकि दक्षिण एशिया में लगभग 16% और उप-सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देशों में 15% से अधिक लोगों में यह रोग पाया गया।

विशेषज्ञों ने बताया कि किडनी रोग सिर्फ गुर्दे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बनता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में हृदय संबंधी कुल मौतों में करीब 12% मौतें किडनी रोग से जुड़ी थीं। यह प्रतिशत मधुमेह और मोटापे जैसे अन्य कारणों की तुलना में कहीं अधिक है, जो इस रोग की गंभीरता को दर्शाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि गंभीर किडनी रोग के पीछे लगभग 14 प्रमुख जोखिम कारक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं — मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा। इसके अलावा फलों और सब्जियों की कमी, अत्यधिक नमक (सोडियम) का सेवन और अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतें भी इस बीमारी के जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में मरीजों में यह रोग तब तक सामने नहीं आता जब तक यह अपने अंतिम चरण में न पहुंच जाए। जब तक मरीज में लक्षण दिखने शुरू होते हैं, तब तक गुर्दे का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा काम करना बंद कर चुका होता है। इसलिए किडनी रोग की शुरुआती पहचान और नियमित जांच बेहद जरूरी है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जनजागरूकता अभियान और जीवनशैली में सुधार से न केवल रोग की गति को रोका जा सकता है, बल्कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी महंगी चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता को भी काफी समय तक टाला जा सकता है।

रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि दुनियाभर में किडनी रोग के इलाज में भारी असमानता मौजूद है। कई देशों में डायलिसिस सेंटर सीमित हैं और ट्रांसप्लांट की सुविधा बहुत महंगी है। विकासशील देशों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां ज्यादातर मरीज इलाज के खर्च के कारण बीच में ही उपचार छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारों और स्वास्थ्य संस्थाओं को अब प्राथमिकता के तौर पर रोकथाम, शुरुआती जांच और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में कदम उठाने होंगे। किडनी रोग के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि न केवल एक चिकित्सा चुनौती है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक दीर्घकालिक संकट का संकेत है।

शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का समय पर इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये ही वो बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे किडनी की कार्यप्रणाली को कमजोर कर देती हैं। कुल मिलाकर, रिपोर्ट ने एक गंभीर चेतावनी दी है — अगर अब भी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दशक में किडनी रोग न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के स्वास्थ्य तंत्र पर भारी बोझ डाल देगा।

अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा, बढ़ेगा दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी मंगलवार को दो दिवसीय भूटान दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा 11 और 12 नवंबर को होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के पारंपरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भारत-भूटान साझेदारी के तहत तैयार किए गए एक बड़े जलविद्युत (हाइड्रोपावर) परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का एक नया अध्याय खोलेगी। पीएम मोदी की यह यात्रा उस समय हो रही है जब दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक संतुलन को लेकर भारत की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोदी के इस दौरे में कई महत्वपूर्ण वार्ताएं होने की संभावना है। वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे से विस्तृत चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के साथ यह बैठक द्विपक्षीय व्यापार, सीमा सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन और जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा के दौरान भारत और भूटान के बीच नई तकनीकी सहायता परियोजनाओं और विकास सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी नए समझौते होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान भूटान के पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे। यह भूटान के लिए एक विशेष अवसर माना जा रहा है और मोदी की उपस्थिति इस रिश्ते की आत्मीयता को और भी गहराई देगी।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा "नेबरहुड फर्स्ट" नीति की निरंतरता का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत साझेदारी और विकास सहयोग पर जोर देता है। भूटान भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और दोनों देशों के बीच दशकों से विश्वास, सम्मान और साझा विकास का रिश्ता रहा है।

राजनयिकों का मानना है कि मोदी की यह यात्रा न केवल भारत-भूटान संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता और सतत विकास के लिए भी एक अहम कदम साबित होगी।

1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 19 दिसंबर तक चलेगा, कुल 15 बैठकें होंगी — सरकार और विपक्ष के बीच अहम मुद्दों पर गर्मा सकता है माहौल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है और विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगा।

पारंपरिक रूप से शीतकालीन सत्र वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है और इसे आगामी आम बजट तथा अगले वित्तीय वर्ष की नीतियों के लिए आधार तैयार करने वाला सत्र माना जाता है। इस बार यह सत्र राजनीतिक रूप से भी खास होने वाला है, क्योंकि देश में पांच राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम — के विधानसभा चुनावों के नतीजे सत्र शुरू होने से ठीक पहले सामने आएंगे। ऐसे में संसद के भीतर राजनीतिक माहौल गर्म रहने की संभावना है।

इससे पहले मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था, जो कई बार विपक्ष के हंगामे और लगातार स्थगन के कारण बाधित रहा। सत्र की शुरुआत में ही राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सत्र का अधिकांश समय विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस में निकल गया। बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और कई अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने बार-बार कार्यवाही रोकने की कोशिश की। लोकसभा में चर्चा के लिए निर्धारित 120 घंटे में से केवल 37 घंटे ही कामकाज हो सका, जबकि राज्यसभा में 41 घंटे तक ही कार्यवाही चल पाई। इसके बावजूद सत्र के दौरान दोनों सदनों में कुल 27 विधेयक पारित किए गए, जिनमें कई अहम रहे। इनमें सबसे चर्चित रहा संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति में उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का निर्णय लिया गया। अब जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ प्रमुख विधेयकों को पेश कर सकती है, जिनमें डिजिटल इंडिया विधेयक, डेटा सुरक्षा कानून, और कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधार विधेयक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आगामी अंतरिम बजट 2025-26 की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी यह सत्र अहम माना जा रहा है। विपक्ष की ओर से भी कई बड़े मुद्दों पर बहस की मांग की संभावना है, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, चीन सीमा विवाद, और आर्थिक असमानता जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं।

मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को मनी लांड्रिंग के एक बड़े मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की 67.03 करोड़ रुपये मूल्य की आठ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है। एजेंसी ने कहा है कि जब्त की गई संपत्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण सीधे तौर पर पीएफआई और उससे जुड़े ट्रस्टों व संगठनों के पास था। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों और पीएफआई से संबद्ध राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नाम पर दर्ज थीं। एजेंसी ने यह भी बताया कि इन संपत्तियों को ऐसे फंड से खरीदा गया था, जिनका स्रोत वैध नहीं पाया गया। बताया गया है कि पीएफआई ने अपने वैचारिक और राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए ट्रस्टों और फ्रंट संगठनों के माध्यम से अवैध धन का उपयोग किया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी सामने आया है कि पीएफआई ने अपने नेटवर्क के जरिए देशभर में कई जगहों पर अचल संपत्तियों का निर्माण किया था और इन संपत्तियों को विभिन्न ट्रस्टों के नाम पर दर्ज कर छिपाने की कोशिश की गई थी। अब तक इस मामले में कुल 129 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को ईडी द्वारा जब्त किया जा चुका है। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इन एफआईआर में पीएफआई और उसके पदाधिकारियों पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, देशविरोधी साजिशों में शामिल होने और अवैध वित्तीय लेनदेन करने के आरोप लगाए गए थे। एजेंसी ने कहा कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई ने विदेशों से धन एकत्र कर भारत में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे विभिन्न ट्रस्टों और संस्थाओं के माध्यम से खर्च किया। इस फंड का उपयोग न केवल संगठन की गतिविधियों के विस्तार के लिए बल्कि नए सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भी किया गया।

सरकार ने वर्ष 2022 में पीएफआई को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से ही इस संगठन से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की जांच ईडी और एनआईए कर रही है। ताजा कार्रवाई को एजेंसियां पीएफआई के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही हैं।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे और भी संपत्तियों की पहचान की जा रही है, और आने वाले दिनों में कई और जब्ती की कार्रवाई संभव है।

समाज में सद्भाव और विश्वास ही राष्ट्र शक्ति का आधार: मोहन भागवत

(जीएनएस)। बेंगलुरु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र की असली शक्ति न तो सेना में है और न ही राजनीति में, बल्कि समाज के भीतर पनपने वाले आपसी विश्वास, सद्भाव और एकता में निहित है। उन्होंने कहा कि जब समाज एकजुट होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तभी देश सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनता है। भागवत शनिवार को बेंगलुरु के बनशंकरी स्थित पीईएस विश्वविद्यालय में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय व्याख्यानमाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ का कार्य केवल विचार या भाषणों तक सीमित नहीं है। संघ का उद्देश्य समाज के भीतर आत्मीयता, एकजुटता और सकारात्मकता को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि समाज जब परस्पर विश्वास से भरा होता है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। "आज हमारे समाज में मतभेद नहीं, संवाद की कमी है। जब हर स्तर पर एक-दूसरे से खुलकर बात होगी, तो गलतफहमियां दूर होंगी और समाज में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा," भागवत ने कहा।

संघ प्रमुख ने सुझाव दिया कि देशभर में विकासखंड स्तर पर विभिन्न जातियों, समुदायों और धार्मिक समूहों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। महीने में एक बार ऐसी बैठकों में आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। "सद्भाव का अर्थ केवल भाषणों से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने से है," उन्होंने कहा।

भागवत ने कहा कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अहंकार छोड़कर उन वर्गों तक पहुंचें जो अब तक मुख्यधारा से दूर रहे हैं। "जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ आत्मीयता का भाव नहीं होगा, तब तक सच्चा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं," उन्होंने कहा।

अपने भाषण में उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय हिंदू और मुस्लिमों की एकता ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। "बहादुर शाह ज़फर ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय समाज में ऐसा विश्वास और एकता थी कि अंग्रेजों ने उसे तोड़ने के लिए विभाजन की नीति अपनाई, जिसके निशान आज भी समाज में मौजूद हैं," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि भारत कोई राजनीतिक संघ नहीं, बल्कि एक संस्कृति-आधारित राष्ट्र है। "आप इसे हिंदू राष्ट्र कहें या भारतीय राष्ट्र, दोनों का अर्थ एक ही है — यह वह भूमि है जिसकी आत्मा हमारी संस्कृति, परंपरा और साझा जीवन मूल्यों में बसती है। जब तक हम इन मूल्यों को जीवित रखेंगे, तब तक भारत विश्व में अग्रणी रहेगा।"

अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए?

जो आपका है उसे वापस दिलाने में आरबीआई आपकी मदद करेगा।

आपके बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से ज़्यादा और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा पैसे / दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप या आपके क़ानूनी वारिस उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

दीया फंड — जागरूकता शिक्षा और जागरूकता निधि

आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण

1. आपके बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, भले ही वो आपकी नियमित शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन के बाद ब्याज समेत, यदि है तो, अपने पैसे वापस पाएं।

दावा न की गई संपत्ति के संबंध में आयोजित विशेष शिविरों में जाएं, जिसे देशभर के सभी ज़िलों में अक्तूबर से दिसंबर 2025 के बीच लगाए जाएँगे।

आपके दावा न किए गए पैसे के बारे में जानने के लिए

आपके बैंक की वेबसाइट पर खोजें या आरबीआई के UDGAM पोर्टल **(https://udgam.rbi.org.in)** पर देखें, जिसमें फ़िलहाल 30 बैंक शामिल हैं।

क्यूआर कोड स्कैन कीजिए

अधिक जानकारी के लिए
https://rbikehtahai.rbi.org.in देखिए
प्रतिक्रिया के लिए **rbikehtahai@rbi.org.in** पर लिखिए

आधिकारिक व्हॉट्सऐप नंबर
99990 41935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन का कहर

पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का शोर तो लंबे समय से सुनाई दे रहा है, लेकिन इसकी घातकता का अंदाजा कुछ समय पहले प्रकाशित प्रमाणिक वैश्विक सर्वेक्षण से सामने आया है। सर्वे बताता है कि भारत में पिछले साल बीस दिन लू का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन कारकों से अधिक गर्म हवाएं चलीं। यह भी कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते 247 अरब घंटों का नुकसान हुआ, जिसके चलते श्रम क्षमता में कमी आने से 194 अरब डॉलर का नुकसान देखा गया। 'द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारकों से कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में बीस फीसदी का नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 अरब डॉलर की संभावित आय का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट विश्व के 71 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 128 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तैयार की, जिसका कुशल नेतृत्व यूनिवर्सिटी कालेज लंदन ने किया। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अब तक सबसे व्यापक आकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की विफलता से लाखों लोगों की जिंदगियां, स्वास्थ्य और आजीविका खतरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापने वाले 20 में से बारह संकेतक अब तक के सबसे उच्चतम स्तर तक जा पहुंचे हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल दस हजार मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। चिंता की बात यह है कि यह वृद्धि 2003 से 2012 की तुलना में 28 फीसदी अधिक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

विडंबना यह है कि 'द लांसेट' की रिपोर्ट में सामने आए गंभीर तथ्यों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से मिलकर जूझने की ईमानदार कोशिश होती नजर नहीं आती। यह निर्विवाद तथ्य है कि दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचने के प्रयास कर रहे हैं। खासकर हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो गैरजिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, उससे नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर इस संकट से निपटने की कोई गंभीर साझा पहल निकट भविष्य में सिरे चढ़ेगी। विकसित देश इस दिशा में मानक पेरिस समझौते की संस्तुतियों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। वे विकास के तमाम संसाधनों का निर्मम दोहन करने के बाद अपनी गरीब आबादी को को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में जुटे विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपायों को लागू करने के लिये लगातार दबाव बना रहे हैं। 'द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट के अनुसार, मानवजनित पीएम-2.5 प्रदूषण भारत में 2022 के दौरान 17 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार था। इसमें कोयला और तरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन का 44 फीसदी योगदान था। इसके साथ ही सड़क परिवहन में पेट्रोल के उपयोग से पैदा प्रदूषण से करीब 2.69 लाख मौतें हुईं। रिपोर्ट में दर्शाई गई सबसे बड़ी चिंता श्रम के घंटों के नुकसान और कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी नुकसान का होना है। यह संकट जहां बड़े विस्थापन को जन्म दे सकता है, वहीं हमारी खाद्य शृंखला संकटग्रस्त हो सकती है, जिसके लिए देश में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों की किस्मों की खोज जरूरी हो जाती है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो फसलों पर जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम किया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने यह मुश्किल सबसे बड़ी है। वहीं भारत सरकार और किसानों के सामने यह वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। 'द लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट में उजागर तथ्य हमारी आंख खोलने वाले व सचेतक हैं।

भारत रत्न आडवाणी ने राजनीति को नई दिशा और मतदाताओं को मजबूत विकल्प दिया

> स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति लम्बे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रही। विपक्ष बिखरा हुआ और असंगठित था। ऐसे समय में आडवाणी ने संगठन के महत्त्व को पहचाना। उन्होंने न केवल भाजपा को संगठित ढाँचा दिया, बल्कि उसे वैचारिक दृढ़ता भी प्रदान की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और लालकृष्ण आडवाणी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें ''एक महान दृष्टिकोण वाला राजनेता'' बताया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को एक मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आज 98 वर्ष के हो गए। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित आडवाणी ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। लालकृष्ण आडवाणी का जीवन भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे युग का साक्षी है, जिसमें कांग्रेस की एकाधिकारवादी राजनीति को पहली बार वैकल्पिक चुनौती मिली।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति लम्बे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रही। विपक्ष बिखरा हुआ और असंगठित था। ऐसे समय में आडवाणी ने संगठन के महत्त्व को पहचाना। उन्होंने न केवल भाजपा को संगठित ढाँचा दिया, बल्कि उसे वैचारिक दृढ़ता भी प्रदान की। उनकी रथयात्रा न केवल भाजपा को जनभावनाओं के केंद्र में लायी बल्कि देश के राजनीतिक विमर्श को ही बदल दिया। जनता को यह विश्वास हुआ कि सत्ता परिवर्तन अब असंभव नहीं है। आडवाणी ने लोकतंत्र को जीवंत प्रतिस्पर्धा का रूप दिया। उन्होंने दिखाया कि विपक्ष केवल आलोचना तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे विकल्प बनना चाहिए— विचार का, नेतृत्व का और नीति का। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान रहा।

आडवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने संगठन को व्यक्ति से ऊपर रखा। उन्होंने नेतृत्व के भीतर सामूहिकता की भावना को पल्लवित किया। भाजपा के विस्तार में उनका योगदान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श से जोड़ा। आपातकाल के दौरान

उनका संघर्ष लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक रहा। जब कई लोग सत्ता के भय में मौन थे, तब आडवाणी ने असहमति को देशभक्ति का रूप दिया। यही साहस आगे चलकर भाजपा के चरित्र का हिस्सा बना।

अविभाजित भारत के कराची में 8 नवंबर 1927 को जन्मे आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। यह पृष्ठभूमि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का आधार बनी यानि अनुशासन, संगठन और राष्ट्रनिष्ठा का त्रिवेणी संगम। आडवाणी का जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफर, किसी राजनीतिक दल की कहानी भर नहीं है; यह उस विचार का प्रस्फुटन है जो यह कहता है कि लोकतंत्र में केवल एक पार्टी का वर्चस्व स्थायी नहीं रह सकता। आडवाणी ने इस सत्य को समझा, जिया और उसे जनांदोलन का रूप दिया।आडवाणी की राजनीति में केवल संघर्ष नहीं, समावेश भी था। जब वह उपप्रधानमंत्री बने, तब भाजपा ने पहली बार बहुदलीय गठबंधन के रूप में सत्ता संभाली। यह भारतीय राजनीति के परिपक्व होने का संकेत था।

उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रीय हित में मतभेद भी सहयोग में बदल सकते हैं। गठबंधन-राजनीति की यह परंपरा भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता की एक बड़ी गारंटी बनी। यह भी सही है कि आडवाणी का राजनीतिक जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। अयोध्या आंदोलन ने उन्हें जहां अपार जनसमर्थन दिलाया, वहीं आलोचना का भी केंद्र बनाया। किंतु यही लोकतंत्र की खूबसूरती है— जहाँ विचारों की विविधता को भी इतिहास दर्ज करता है। आडवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उन्होंने विवाद से विमर्श की दिशा निकाली। वह संवाद को टकराव से ऊपर मानते हैं। आज भारतीय लोकतंत्र में भाजपा के रूप में जो सशक्त वैकल्पिक शक्ति खड़ी है, उसकी नींव एक तरह से आडवाणी ने ही रखी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिस्पर्धा का उत्सव है। उनकी राजनीति ने जनसंघ से भाजपा तक एक ऐसी यात्रा तय की जिसमें विचार, संगठन और जनविश्वास एक सूत्र में बंधे। देखा जाये तो राजनीति में कुछ ही ऐसे नेता होते हैं, जिनके कार्य और दृष्टि केवल किसी दल को नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा देते हैं। लालकृष्ण आडवाणी निस्संदेह उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को संगठनात्मक रूप से सशक्त किया, बल्कि हिंदुत्व की सांस्कृतिक चेतना को राजनीतिक अभिव्यक्ति में बदलने का ऐतिहासिक कार्य भी किया। उनके नेतृत्व में जन्मा और विस्तृत हुआ राम मंदिर आंदोलन, आधुनिक भारत के सबसे बड़े और दीर्घकालिक जनआंदोलनों में से एक माना जाता है। खास बात यह रही कि राम मंदिर आंदोलन अपने लक्ष्य में सफल भी रहा क्योंकि श्रीरामजन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ।देखा जाये तो आडवाणी का राजनीतिक दृष्टिकोण केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की गहराइयों में विद्यमान सांस्कृतिक अस्मिता को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मुद्दा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। आडवाणी ने इसे राष्ट्र की आत्मा से जोड़ा और इसे "राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न" कहा। उनकी 1990 की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक चली, उसने हिंदू समाज को आत्म-स्वर देने का कार्य किया। यह यात्रा मात्र राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मानस को आंदोलित करने वाली यात्रा थी। जहां भी रथ पहुँचा, वहां लाखों की भीड़ एक विचार से जुड़ने लगी— "राम हमारे हैं, राम राष्ट्र के हैं।" यही वह बिंदु था जिसने भाजपा को विचार की पार्टी से जनांदोलन की पार्टी बना दिया। साथ ही 1980 के दशक में भाजपा जब अपने आरंभिक चरण में थी, तब वह महज दो सीटों तक सीमित रह गई थी। ऐसे कठिन समय में आडवाणी ने पार्टी को सिद्धांतों से जोड़े रखने और संगठन को विस्तार देने की दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने जनसंघ की अनुशासन परंपरा को आगे बढ़ाया और पार्टी में विचारधारा को प्राथमिकता देने का संस्कार विकसित किया। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सांगठनिक संरचना को नई ऊंचाई दी और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नेटवर्क को मजबूत किया, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को सक्रिय किया और विचार-विस्तार के लिए "पार्टी विद ए डिफरेंस" की अवधारणा दी। यही संगठनात्मक शक्ति बाद में भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय स्तंभ बना गई।

आडवाणी ने हिंदुत्व को कभी धार्मिक अवधारणा के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे "राष्ट्रीय पहचान का सांस्कृतिक बोध" कहा यानि एक ऐसी चेतना जो भारतीयता को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुत्व भारत के जीवन-मूल्यों का प्रतीक है, जो सहिष्णुता, समरसता और आध्यात्मिकता का संगम है। यही दृष्टिकोण उन्हें एक सांस्कृतिक राजनेता के रूप में अलग करता है। उन्होंने "सकारात्मक राष्ट्रवाद" की अवधारणा प्रस्तुत की, जो किसी के विरोध पर नहीं, बल्कि अपने गौरव के पुनर्स्थापन पर आधारित थी।

आडवाणी की राम रथ यात्रा, स्वर्ण जयंती यात्रा और भारत गौरव यात्रा सिर्फ राजनीतिक आयोजन नहीं थीं। वे संवाद के साधन थे, जिनसे भाजपा ने जनता के बीच अपनी वैचारिक उपस्थिति दर्ज कराई। इन यात्राओं ने भाजपा को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में स्थापित किया। 1990 की रथ यात्रा ने जहां भाजपा को एक सांस्कृतिक मिशन दिया, वहीं 1997 की स्वर्ण जयंती यात्रा ने पार्टी को प्रशासनिक और शासन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

प्रेरणा

गुणों से बढ़कर नहीं होता कोई सम्मान

नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का वह सम्राट जिसने अपने पराक्रम, साहस और शासनकला से पूरे यूरोप को झुका दिया था, एक दिन अपने विशाल दरबार में बैठा राज्य के कामकाज में व्यस्त था। तभी एक साधारण-सा व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा साधारण है, जूते घिसे हुए हैं और बाल अस्त-व्यस्त हैं। दरबारी उसे देखकर मुस्कराने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति सम्राट से मिलने आया है।

जब वह व्यक्ति नेपोलियन के समीप पहुँचा, तो नेपोलियन ने एक नज़र उस पर डाली और कुछ क्षण के लिए उसे देखा, फिर नज़रें हटा लीं। उसके मन में यह विचार आया कि यह कोई महत्वहीन व्यक्ति होगा जो किसी अनुचित आग्रह से मिलने आया है। नेपोलियन ने औपचारिकता निभाते हुए उससे ठंडे स्वर में पूछा, "कहो, तुम कौन हो और किसलिए आए हो?"

वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, "महाराज, मैं एक चित्रकार हूँ। आपके राज्य में मेरी चित्रकला की प्रदर्शनी लगी थी। मैंने सुना कि आप कला के बड़े प्रशंसक हैं, इसलिए आपकी अनुमति से आपका चित्र बनाना चाहता हूँ।"

नेपोलियन ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, "चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम जैसे मैले-कुचैले कपड़े पहनकर कोई कलाकार मेरे दरबार में कैसे प्रवेश कर गया?" यह सुनकर दरबारियों में हल्की हँसी फैल गई, लेकिन वह चित्रकार शांत बना रहा। उसने नम्रता से कहा, "महाराज, वस्त्र शरीर की शोभा हैं, किंतु कला आत्मा की। कलाकार की महानता उसके कपड़ों से नहीं, उसकी कृति से पहचानी जाती है।"

नेपोलियन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने आदेश दिया कि उसके चित्र दरबार में लाए जाएँ। कुछ ही देर में जब चित्र प्रस्तुत किए गए, तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो उठा। चित्रों में जीवन झलक रहा था, रंगों में भावनाओं की गहराई थी, और आकृतियों में ऐसी सुंदरता कि नेपोलियन स्वयं आश्चर्यचकित रह गया।

नेपोलियन ने उन चित्रों को देखा और उसकी आँखों में सम्मान उतर आया। उसने चित्रकार को अपने पास बुलाया, और इस बार उसके स्वर में विनम्रता थी। उसने कहा, "तुम्हारे चित्रों में जो आत्मा है, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तुम सच में महान कलाकार हो।" चित्रकार ने मुस्कराकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, "महाराज, मैं तो केवल अपने भावों को रंगों में उतारता हूँ। यदि वे लोगों के हृदय को छूते हैं, तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।"

कुछ देर बाद जब चित्रकार जाने के लिए उठा, तो नेपोलियन स्वयं अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट स्वयं एक साधारण चित्रकार को द्वार तक छोड़ने जा रहा था। चित्रकार ने आश्चर्य से पूछा, "महाराज, जब मैं आया था, तब आपने मुझसे बात तक नहीं की थी, लेकिन अब आप स्वयं मुझे विदा करने आए हैं, इसका क्या कारण है?" नेपोलियन मुस्कुराते हुए बोला, "जब तुम मेरे पास आए थे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों से परख रहा था। पर अब जब तुम जा रहे हो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों से पहचान रहा हूँ। आने वाले का सम्मान अक्सर उसके पहनावे से होता है, पर जाने वाले का सम्मान उसके कर्मों से होता है।" यह सुनकर चित्रकार के नेत्र नम हो गए। उसने झुककर प्रणाम किया और चला गया। नेपोलियन काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा — कि कितना बड़ा भ्रम है यह संसार का, जो वस्त्रों को प्रतिष्ठा और पद को मूल्य मानता है।

इस घटना नेपोलियन को भी भीतर से बदल गई। उसने उसी दिन से यह निर्णय लिया कि वह किसी का मूल्यांकन उसके रूप, वस्त्र या स्थिति से नहीं करेगा, बल्कि उसके कर्मों और गुणों से करेगा।

यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि सच्चा सम्मान किसी की संपत्ति, वेशभूषा या पद से नहीं जुड़ा होता। यह उन अदृश्य गुणों से जुड़ा होता है जो किसी व्यक्ति को वास्तव में महान बनाते हैं। वस्त्र और रूप अस्थायी हैं, पर ज्ञान, कला, और विनम्रता अमर हैं। जो व्यक्ति अपने गुणों से सम्मान अर्जित करता है, उसका आदर युगों तक जीवित रहता है। जबकि जो केवल बाहरी दिखावे पर गर्व करता है, उसका नाम समय के साथ मिट जाता है। इसलिए सच्चा सम्मान पाने की चाह रखने वाले को अपने भीतर के गुणों का विकास करना चाहिए — क्योंकि वस्त्र उतर जाते हैं, पद छिन जाते हैं, लेकिन गुण सदा मनुष्य के साथ रहते हैं, और वही उसे सम्मान दिलाते हैं।

रेल सुरक्षा: सुधार की पटरियों पर कब चढ़ेगा सिस्टम?

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है, जिसने सुरक्षा को केवल एक चुनावी 'घोषणापत्र' सरीखा बनाकर रख दिया है। बिलासपुर के लालखदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी 'कागज पर कवच' से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे की भयावहता के साथ ही जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं, तो एक सिहरन सी उठती है। महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा तो इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, 'दोषियों पर कार्रवाई होगी', 'मुआवजा दिया जाएगा', 'जांच समिति गठित की गई है', और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल 'प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र' बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी कि या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से 'कवच' सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। रेल प्रशासन का रवैया भी उतना ही असंवेदनशील है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी जाती है लेकिन यह मुआवजा न किसी बच्चे को उसका पिता लौटा सकता है, न किसी पत्नी को उसका पति, न किसी मां को उसका बेटा। जरूरत मुआवजे की नहीं, जवाबदेही की है। यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को 'विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था' कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटनां के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या वंदे भारत उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

अभियान

जब श्रीकृष्ण की चालीसा से बदल गया जीवन का भाग्य

वृंदावन की पावन नगरी में राधे-श्याम का नाम हर प्रातःकाल गली-गली में गूंजता है। वहां एक वृद्ध भक्त रहते थे — नाम था नंददास। उनके घर की हालत बहुत साधारण थी। कभी-कभी तो रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था, फिर भी उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनके जीवन का एक ही आधार था — भगवान श्रीकृष्ण का नाम और उनकी भक्ति। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगाजल से स्नान करते, तुलसी के पौधे को प्रणाम करते और फिर श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करते।

उनके पड़ोसी अक्सर कहते, "नंददास, भक्ति से पेट नहीं भरता। कुछ काम धंधा भी कर लो।" लेकिन नंददास मुस्कराकर उत्तर देते, "मुझे विश्वास है कि जो माखनचोर सबका पालन करता है, वह मुझे भूखा नहीं रखेगा। बस मैं उसका नाम नहीं छोड़ूंगा।"

एक बार ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक उनके घर में कोई भोजन नहीं था। उनके पास एक अन्न का दाना भी नहीं बचा। उनकी पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, "अब तो कुछ चमत्कार ही हमें बचा सकता है।" नंददास ने शांत स्वर में कहा, "चमत्कार वही करेगा जो हर दिन मेरे साथ बैठकर मेरी चालीसा सुनता है।" उन्होंने उसी दिन पहले से भी अधिक भक्ति भाव से श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ किया। जैसे ही उन्होंने "जय कन्हैया लाल की" कहा, अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उन्होंने बाहर जाकर देखा — एक सुंदर युवक खड़ा था, जिसने पीले वस्त्र पहने थे, गले में मोरपंख और हाथ में बांसुरी थी। युवक ने मुस्कराकर कहा, "बाबा, मैं मथुरा जा रहा था, रास्ते में थकान लग गई। क्या मुझे कुछ देर आपके द्वार पर विश्राम मिल सकता है?" नंददास ने आदरपूर्वक कहा, "श्याम! मेरा घर तो तेरे जैसा अतिथि आने से ही पवित्र हो गया। आओ।"

युवक अंदर आया और बोला, "मैंने रास्ते से कुछ फल, दूध और मिठाइयां खरीदी हैं। चलिए, हम सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करें।" नंददास और उनकी पत्नी ने आश्चर्य से देखा कि घर में जहाँ पहले कुछ नहीं था, अब पूरा भोजन भरा पड़ा है। उन्होंने आँसुओं से भरी आँखों से कहा, "कन्हैया! तू ही तो है ना?" युवक ने मुस्कराकर

कहा, "बाबा, तुम रोज मेरी चालीसा पढ़ते हो, मैं कैसे न आता? जब भक्त पुकारता है, तो गोविंद स्वयं चला आता है।"

इतना कहकर वह युवक अचानक अदृश्य हो गया। कमरे में मुरली की मधुर ध्वनि गूंज उठी, और वातावरण में तुलसी, चंदन और माखन की सुगंध भर गई। उस दिन के बाद नंददास के घर से कभी अन्न की कमी नहीं हुई। धीरे-धीरे उनका जीवन बदल गया। वे कहते थे, "कान्हा केवल मंदिर में नहीं, वह हर उस हृदय में बसता है जो उसे प्रेम से पुकारता है।"

इस घटना के बाद पूरे वृंदावन में श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ एक नियम बन गया। लोग कहते थे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सच्चे मन से इस चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और क्लेश मिट जाते हैं। घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। विद्यार्थियों को बुद्धि और एकाग्रता मिलती है, दंपत्तियों को संतान सुख मिलता है, और व्यापारियों के कामों में वृद्धि होती है।

कहा जाता है कि श्रीकृष्ण चालीसा के प्रत्येक छंद में दिव्य शक्ति निहित है। जब भक्त उसकी हर पंक्ति को श्रद्धा से बोलता है, तो कान्हा के चरण स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। उनके नाम का उच्चारण ही ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो मन को स्थिर, हृदय को निर्मल और जीवन को प्रकाशमय बना देती है।

कान्हा का वचन है — "जो मुझे सच्चे भाव से याद करता है, मैं उसके हर संकट में साथ रहता हूँ।" इसलिए जो व्यक्ति रोजाना श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण स्थापित होता है।

नंददास की तरह जो भक्त बिना अपेक्षा के केवल प्रेम से श्रीकृष्ण की आराधना करता है, उसके जीवन में हर कठिनाई सरल बन जाती है। श्रीकृष्ण का नाम ही ऐसा मंत्र है जो दुख को सुख में, क्लेश को कृपा में, और अंधकार को प्रकाश में बदल देता है।

इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता चाहता है, वह रोज श्रद्धा और प्रेम से श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ करे। जब मन सच्चे भाव से "जय श्रीकृष्ण" कहेगा, तो मुरलीधर स्वयं उसके जीवन की धुन को मधुर बना देंगे।

क्योंकि जो भक्त कान्हा को पुकारता है, उसे उत्तर देने में कभी देर नहीं होती —

वह स्वयं आकर कह देता है,

"भक्त जहाँ, वहीं मैं हूँ।"

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

गुजरात आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

- जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट : आदिवासी समुदाय के आनुवंशिक रोगों की पहचान होने से किफायती निदान पद्धति का विकास होगा, 1 लाख रुपए के बजाय केवल 1000-1500 रुपए में होगा परीक्षण
- गुजरात की अत्याधुनिक जीनोम सुविधा: 48 से 72 घंटे में होती है 25-50 नमूनों की सीक्वेंसिंग
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध

(जीएनएस)। गांधीनगर, 08 नवंबर : गुजरात ने आदिवासी लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प किया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की अस्मिता, आत्मसम्मान और बहादुरी के प्रतीक हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की पहल शुरू की है। श्री मोदी दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि जब हमारे आदिवासी समुदाय समृद्ध होंगे, तो भारत भी समृद्ध होगा। उनके इस विजन का अनुसरण करते हुए गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गुजरात के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप गुजरात, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जीनोम सीक्वेंसिंग (अनुक्रमण) प्रोजेक्ट शुरू किया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग और आदिवासी समुदाय के लिए इसका महत्व

शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद आनुवंशिक सामग्री को जीनोम कहा जाता है। कोशिका के अंदर जीन का सटीक स्थान और उसकी रचना को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यह जीनोम में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। गुजरात की आदिवासी आबादी लंबे समय से थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रही है। कुछ आनुवंशिक बीमारियां ऐसी होती हैं, जिनके बारे में आखिरी स्टेज तक पता नहीं चल पाता, जिससे उपचार और अधिक जटिल हो जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से वैज्ञानिक म्यूटेशन (परिवर्तनों) का पता लगा सकते हैं, कम लागत वाले डायग्नोस्टिक पैनल बना सकते हैं, और आईवीएफ प्रक्रियाओं के दौरान प्रसवपूर्व या फिर भ्रूण-स्तरीय परीक्षण भी कर सकते हैं।

जीनोम मैपिंग के जरिए आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार का संकल्प

यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों का स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करते हुए बेहतर स्वास्थ्य-उन्मुख योजनाएं बनाने में मदद करेगा। इससे बीमारियों का पता लगाने, कुपोषण और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने तथा सिकल सेल एनीमिया एवं ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज (जी6पीडी) की कमी जैसे आनुवंशिक विकारों का शीघ्र निदान संभव होगा।

उदाहरण के लिए, यदि माता और पिता, दोनों में बीटा-ग्लोबिन जीन (जिसे वाहक कहा जाता है) की एक म्यूटेटेड कॉपी है, तो इस बात की 25 फीसदी संभावना है कि उनके बच्चे को दोनों म्यूटेटेड कॉपियां विरासत में मिलेगी, जिसके चलते सिकल सेल रोग विकसित होगा। जीनोम मैपिंग के माध्यम से ऐसे वाहकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है, जिससे रोग के बारे में शीघ्र पता लगाया जा सके और निवारक उपाय किए जा सकें। इससे समुदाय के आनुवंशिक लक्षणों के अनुसार डीएनए परीक्षण तैयार किया जा सकता है। ये परीक्षण केवल संबंधित समुदाय में आम तौर पर होने वाले जीन परितवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसका खर्च केवल 1000 से 1500 रुपए तक होता है। इसकी तुलना में, संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग व्यक्ति के सभी जीनों की पहचान करता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है और एक्सोम सीक्वेंसिंग केवल जीन के कोडिंग हिस्सों को पढ़ता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 18,000 से 20,000 रुपए का खर्च होता है। इस प्रकार, समुदाय-विशिष्ट परीक्षण ज्यादा व्यावहारिक और कम खर्चीले होते हैं।

गुजरात जीनोम सीक्वेंसिग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने विशेष आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों के आनुवंशिक खाके (जेनेटिक ब्लूप्रिंट) का अध्ययन करके रोग के परीक्षण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। उल्लेखनीय है कि जीनोम इंडिया पहल के तहत कार्यरत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों आदिवासी समुदायों में आनुवंशिक विकृतियां बढ़ रही हैं, जो अक्सर अंतर्विवाह (अपने ही समूह में विवाह) और सीमित आनुवंशिक विविधता के कारण होते हैं।

11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों के डीएनए नमूने एकत्र किए जाएंगे

गुजरात में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत शोधकर्ता 11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों में से डीएनए के नमूने एकत्र कर एक डेटाबेस बना रहे हैं, जो इन समूहों में आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार के तरीकों को सुधारने में मदद करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, गुजरात सरकार ने एक व्यापक जीनोम डेटाबेस बनाने और मौजूदा डेटा अंतराल को पाटने के लिए 'आदिवासी आबादी के लिए रेफरेंस जीनोम डेटाबेस का निर्माण' प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के सहयोग से चलाय जा रहा है।

आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम विज्ञान का उपयोग करने में गुजरात अग्रणी

गुजरात में जीनोम अनुसंधान को गति देने के लिए जीबीआरसी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें लॉन्ग-रीड सीक्वेंसर सहित तीन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें शामिल हैं, जो एक समय में 5000-10,000 बेस पेयर (मूल जोड़े) का विश्लेषण कर सकती है, जिससे वैज्ञानिकों को जटिल आनुवंशिक बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। इन मशीनों का उपयोग पहले कोविड-19 के दौरान किया जाता था, लेकिन अब इनका उपयोग व्यापक जीनोम अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। गुजरात में, प्रत्येक सीक्वेंसिंग बैच 25-50 मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकता है, इसके परिणाम 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाते हैं। जीबीआरसी ने लागत प्रबंधन और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके प्रति नमूना खर्च 85,000 रुपए से घटाकर लगभग 60,000 रुपए कर दिया है। यह अनुसंधान डॉक्टरों को सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी उपचार प्रदान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आदिवासी समुदाय को आधुनिक जीनोम विज्ञान का लाभ मिले।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में रविवार को जूनागढ से राज्यव्यापी पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च - पदयात्रा का आयोजन तथा आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली जाएगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 9 नवंबर रविवार को यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाली राज्यव्यापी पदयात्रा का जूनागढ से प्रारंभ कराएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग तथा जूनागढ जिला प्रशासन के उपक्रम से इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में 9 नवंबर को जूनागढ नवाबी शासन से स्वतंत्र हुआ था और उसका भारत में विलय हुआ था, जिसे जूनागढ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान से जूनागढ का भारत में विलय कराए जाने के इस यादगार दिवस के समय ही इस वर्ष मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में इस पदयात्रा का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार सुबह 7 बजे इस पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे। इस अवसर पर जूनागढ जिला प्रभारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा, जिला सह प्रभारी विधि राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, जूनागढ के महापौर श्री धर्मेश पोशिया, विधायक तथा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस पदायात्रा में समाज के सभी वर्ग, कॉलेज छात्र, एनसीसी, एनएसएस, माई भारत वॉलेंटियर्स, सहकारी संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल, औद्योगिक संगठन, वाणिज्यिक संगठन, धार्मिक संस्थान, स्थानीय साधु-संत, इन्फ्लूएंसर्स, पूर्व सैनिक एवं परिवार, खिलाड़ी, प्रगतिशील किसान, प्रबुद्ध नागरिक, कामगार, सामाजिक संस्थाएँ, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, स्वयं-सहायता समूह तथा बड़ी संख्या में नागरिक सहभागी होंगे और आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेंगे।

प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के विश्वामित्री – डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 09 नवम्बर 2025 से 13 नवम्बर 2025 तक कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार है:

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1. ट्रेन नं 69202 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी
2. ट्रेन नं 69203 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी
3. ट्रेन नं 59122 छोटाउदैपुर - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी
4. ट्रेन नं 59125 प्रतापनगर – छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

देश की प्रगति का इंजन है बरेका, लोको निर्माण की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं: अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)। वाराणसी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) का विस्तृत निरीक्षण करते हुए कहा कि भारतीय रेल के लिए गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और लोको निर्माण में किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि "बरेका केवल लोकोमोटिव नहीं बनाता, बल्कि यह भारत की प्रगति के इंजन को गति देता है।"

निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने लोको फ्रेम शॉप, असेम्बली शॉप और टेस्ट शॉप का दौरा किया। उन्होंने प्रत्येक निर्माण इकाई में जाकर उत्पादन प्रक्रिया की बारीकियों को समझा और कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संवाद किया। मंत्री ने मशीनों के रखरखाव, स्वचालित तकनीक के प्रयोग, ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय रेल आज जिस आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसका मूल आधार ही गुणवत्ता और नवाचार है। अश्विनी वैष्णव ने निर्माण इकाइयों में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों से भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और निर्माण लागत घटाने के सुझाव आमंत्रित किए। रेल मंत्री ने कहा कि "गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव अमूल्य हैं। यदि हर कर्मचारी अपने काम में नवाचार की भावना रखे, तो भारतीय रेल विश्व की सबसे आधुनिक रेल प्रणाली बन सकती है।" निरीक्षण के दौरान मंत्री ने महिला कर्मचारियों से विशेष रूप से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में महिलाओं की भूमिका लगातार सशक्त हो रही है। "बरेका की महिला इंजीनियर और तकनीशियन जिस दक्षता से काम कर रही हैं, वह न केवल संगठन के लिए प्रेरणादायक है बल्कि यह भारत की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी है," उन्होंने कहा।

रेल मंत्री ने बरेका की स्वच्छता व्यवस्था, हरित ऊर्जा प्रयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बरेका का प्रयास केवल तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण नहीं, बल्कि एक "ग्रीन इंडस्ट्री मॉडल" के रूप में भी देश के सामने है। कर्मचारियों के साथ संवाद के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के पास अब लोकोमोटिव निर्माण में विश्व स्तरीय क्षमता है।

150th JANJATIYA GAURAV VARSH

भगवान बिरसा मुंडा की १५०वीं जन्म जयंती

जनजातीय गौरव वर्ष

पोषण से शक्ति, शिक्षा से प्रगति

'शिक्षण' की उत्तम सुविधाओं एवं 'दूध संजीवनी' जैसी योजनाओं द्वारा आदिजाति विद्यार्थियों के सर्वांगी विकास का संकल्प

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष २००७ में आदिजाति क्षेत्र के सर्वांगी विकास के लिए शुरू की गई वनबंधु कल्याण योजना

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा वनबंधु कल्याण योजना -२ (वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६) के लिए ₹ १ लाख करोड़ की राशि आवंटित

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

"हर घर स्वदेशी
घर-घर स्वदेशी"

शैक्षणिक विकास और पोषण की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (वर्ष २०२०-२१ से २०२४-२५):

- मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सिलेंस के तहत अनुमानित ₹ १,६३३ करोड़ की लागत से ८,१९५ नए कक्षाओं का निर्माण तथा अनुमानित ₹ ६०० करोड़ की लागत से १२,०१० कक्षाओं की मरम्मत
- प्रतिवर्ष अनुमानित १२ लाख आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुमानित ₹ ८०० करोड़ की सहायता
- कक्षा ९ में अध्ययन करने वाली १.५८ लाख आदिजाति कन्याओं को विद्या साधना योजना के तहत साइकिल वितरण
- दूध संजीवनी योजना के तहत अनुमानित ₹ २३२.९१ करोड़ की लागत से प्रतिवर्ष लगभग ७ लाख आदिजाति बच्चों को २०० मिली फ्लेवर्ड दूध वितरण की सुविधा

आदिजाति विकास विभाग, गुजरात सरकार

‘वो बच्चों को कट्टा देते हैं और हम लैपटॉप’ — पीएम मोदी का RJD पर तीखा प्रहार, कहा बिहार अब जंगलराज नहीं, विकास चाहता है

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में दो विशाल चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए विपक्ष, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एनडीए युवाओं को लैपटॉप, कंप्यूटर और खेल उपकरण दे रहा है, जबकि राजद उन्हें कट्टा और गुंडागर्दी की राह दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार ने बहुत देखा है — अब राज्य को स्टार्टअप और तकनीक की दिशा में आगे बढ़ना है, न कि फिर से अंधकार और हिंसा की ओर लौटना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज राजद का समर्थन कर रहे हैं, वे अपने परिवार के बच्चों को मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और विधायक बनाना चाहते हैं, जबकि आपके बच्चों को रंगदार और अपराधी बनाने की राह पर धकेलना चाहते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार की जनता अब बहुत जागरूक है, वो यह भेद अच्छे से समझती है। उन्होंने कहा कि बिहार ने दशकों पहले जंगलराज देखा है — जहां पिस्तौल, क्रूरता, भ्रष्टाचार और जातिगत दुश्मनी का बोलबाला था। अब बिहार के लोग विकास, शिक्षा, उद्योग और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में वायरल हुए एक वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें एक बच्चा राजद की रैली में “रंगदार बनना है” जैसे नारे लगाता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वीडियो इस बात का साक्ष्य है कि राजद बिहार के भविष्य यानी बच्चों के साथ क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों को अपराध और हिंसा की भाषा सिखाना, यह बिहार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने जनता से प्रश्न किया, “क्या आप अपने बच्चों को अपराध की राह पर ले जाने देंगे या शिक्षा, रोजगार और प्रगति की ओर बढ़ने देंगे?”

उन्होंने मंच से कहा कि “एनडीए की सरकार जहां आपके बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप और खेल उपकरण दे रही है, वहीं राजद आपके हाथों में कट्टा देना चाहती है। बिहार को अब ‘हाथ ऊपर करो’ कहने

वालों की नहीं, अपने सपनों को साकार करने वालों की जरूरत है।” इसी संदर्भ में उन्होंने नया नारा दिया — “नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार।” इस नारे को भीड़ ने जोरदार समर्थन के साथ दोहराया।

पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की भी सराहना की और पहले चरण के मतदान में भारी मतदान को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि छह नवंबर को हुए पहले चरण में भारी मतदान ने विपक्ष को जोर का झटका दिया है और यह साफ संकेत है कि जनता एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज बिहार को फिर से हिंसा और पिछड़ेपन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि नया बिहार अब सपनों से भरा है। उन्होंने कहा कि “बिहार अब उद्योग चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है। अब हर युवा स्टार्टअप का सपना देख रहा है, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक नया परिवर्तन आ रहा है।” उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य को नई सड़कें, रेल नेटवर्क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी दी है, और आने वाले पांच वर्षों में बिहार को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने वर्षों तक बिहार को जात-पात और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए की राजनीति विकास की है, जबकि विपक्ष की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि 11 नवंबर को मतदान के दिन घर से निकलें और विकास, शांति और स्थिरता के पक्ष में वोट करें। प्रधानमंत्री मोदी अब तक बिहार में करीब एक दर्जन चुनावी रैलियां कर चुके हैं और हर रैली में उन्होंने एनडीए के विकास एजेंडे को केंद्र में रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब उस दौर से बाहर आ चुका है जब बंदूक की आवाज़ें विकास की आवाज़ों को दबा देती थीं। अब बिहार में सिर्फ प्रगति की बात होगी, न कि अपराध की।

बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को भारी बहुमत देकर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी।

भारत पर्व-2025, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर : ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’

एकता नगर के प्रकाश पर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का प्रतीक ‘ग्रीन ट्री’ बना आकर्षण का केन्द्र

▸▸ भारत पर्व-2025 के थीम पैवेलियन का मुख्य आकर्षण ‘ग्रीन ट्री’ विकास, टेक्नोलॉजी तथा एकता का झिलमिलाता प्रतीक

▸▸ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को उजागर करने वाला ‘ग्रीन ट्री’ प्रकाश एवं प्रगति का अनूठा प्रदर्शन

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के एकता नगर में भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के सहयोग से विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के परिसर में भव्य भारत पर्व-2025 का आयोजन हुआ है। यह पहली बार है कि भारत पर्व दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात ने इस पर्व को भव्यता दी है। इस पर्व के दौरान देश की विविधता में एकता का प्रतीक दर्शाने वाले सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजिकल तथा देशभक्ति से प्रेरित कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।

भारत पर्व-2025 के थीम पैवेलियन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुए विभिन्न राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तथा विकास के प्रतीकों को अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पैवेलियन का मुख्य आकर्षण ‘ग्रीन ट्री’ है, जो विकसित भारत के सपने को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। प्रकाशित इन्स्टॉलेशन के रूप में खड़े इस ग्रीन ट्री द्वारा भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा एवं प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। इस दृश्यावली ने देशभक्ति, आर्ट तथा टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम सृजित किया है; जो देश-विदेश के पर्यटकों को अद्भुत अनुभूति कराता है। ‘ग्रीन ट्री’ इन्स्टॉलेशन में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन के तहत साकार हुए राष्ट्रीय स्तर के माइल स्टोन प्रोजेक्ट्स को प्रकाशित ढंग से प्रस्तुत किया गया है; जैसे कि सूरत डायमंड बोर्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेजस फाइटर जेट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑपरेशन सिंदूर, लक्षद्वीप विकास, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी, महाकुंभ-2025, आईएनएस विक्रांत, सोनमर्ग टनल, विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तथा अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स। ये सभी प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने वाले प्रतीकात्मक चरणों के रूप में झिलमिलाते हैं।

भारत पर्व के समग्र परिसर में प्रकाश, संगीत तथा टेक्नलॉजी का समन्वय देशभक्ति की लहर फैलाता है। ‘ग्रीन ट्री’ केवल एक कलात्मक इन्स्टॉलेशन नहीं है; बल्कि भारत के विकास, प्रगति तथा पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। इसमें दर्शाया गया प्रत्येक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के नेशन बिल्डिंग विजन का दृश्यरूपी साकार स्वरूप है। ‘ग्रीन ट्री’ यानी भारत के सपने का विकसित वटवृक्ष। एकता नगर में भारत पर्व के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की लोककला, संगीत, नृत्य एवं परंपरा का मनोहर प्रदर्शन हुआ है; जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की जीवंत अनुभूति कराता है। इस प्रकाश पर्व-2025 के माध्यम से भारत के विकास एवं एकता का अद्भुत दृश्य सृजित हुआ है; जो राष्ट्रप्रेम, गौरव तथा भविष्य के प्रति विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाता है। भारत पर्व-2025 केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने वाला राष्ट्रीय प्रदर्शन है। एकता नगर का यह प्रकाश पर्व भविष्य के उज्ज्वल भारत का संदेश दे रहा है; जहाँ प्रगति, एकता तथा देशभक्ति एक साथ झिलमिलाते हैं।

हत्या में हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों दोषियों की आजीवन सजा बरकरार

(जीएनएस)। कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या के मामलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद नहीं होता, तो केवल इस आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि हत्या वास्तव में हुई है और अपराधियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है, तब तक हथियार की बरामदगी का न होना न्याय में बाधक नहीं है।

न्यायमूर्ति देबांशु घोष और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने 1999 में हुई एक हत्या के मामले में यह टिप्पणी करते हुए तीनों अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि अपराधियों ने जानबूझकर हत्या की थी।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, “जब सबूतों से यह साबित हो जाता है कि पीड़ित की मृत्यु हत्या के कारण हुई है, तब मात्र हथियार की बरामदगी न होना या आर्म्स एक्ट के तहत अलग से आरोप न लगना अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाता।” न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हों, तो हत्या के पीछे के मकसद (मोटिव) का अभाव भी अभियोजन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता।

मामले के अनुसार, 19 जून 1999 को श्रीदाम घोष नामक व्यक्ति अपने दो भाइयों के साथ गंगा नदी में नाव से यात्रा कर रहे थे। उसी नाव में आरोपी धनु घोष और उसके दो साथी भी सवार थे। आरोप है कि अचानक धनु घोष श्रीदाम के पास गया और पाइप गन से उनके गले में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई गोपीनाथ घोष ने केतुग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लंबी सुनवाई के बाद 2022 में कटवा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष हत्या को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि न तो हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ और न ही गोली मिली। उनका कहना था कि सजा अनुमान पर आधारित है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं और घटनास्थल की परिस्थितियां भी अभियोजन के दावों की पुष्टि करती हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष द्वारा पुराने झगड़ों और मुकदमों का हवाला देकर “झूठे फंसाने” की जो दलील दी गई, वह स्वयं उनके खिलाफ जाती है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि हत्या पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान न केवल विश्वसनीय हैं बल्कि एक समान भी हैं, जो अभियुक्तों की संलिप्तता को संदेह से परे साबित करते हैं।

अंततः अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए तीनों अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और कहा कि “न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल तकनीकीताओं पर नहीं, बल्कि सच्चाई और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना है।”

भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत आने वाले भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ दिनांक 08 नवम्बर, 2025 को किया गया।

इस स्टॉल का उद्घाटन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव श्री एस. के. श्रीवास्तव, मंडल वाणिज्य निरीक्षक श्री तुषार शेख, मंडल परिचालन निरीक्षक श्री संजय सिंह, स्टेशन अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार, रेलवे कर्मचारीगण एवं रेल यात्री उपस्थित रहे।

उद्घाटन अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कैटरिंग स्टॉल के लाइसेंसी श्री आकाश कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने श्री आकाश कुमार को प्रोत्साहित करते हुए स्टॉल से खरीददारी भी की। उपस्थित अन्य कर्मचारियों एवं यात्रियों ने भी स्टॉल से खाने-पीने की वस्तुएं क्रय कर स्थानीय स्तर पर शुरू की गई इस सुविधा की सराहना की। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस स्टॉल के खुलने से भावनगर परा स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छ, ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित दरों पर प्राप्त होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में और अधिक वृद्धि होगी। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशनों पर विभिन्न सेवाओं के विस्तार की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।

मछुआरों की पहचान होगी अब डिजिटल, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नए नियमों से खुलेगा विकास का समंदर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के लाखों मछुआरों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत और आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत की है। समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को अधिक संगठित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब प्रत्येक मछुआरे को क्यूआर कोड युक्त आधार कार्ड या फिशर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उनकी पहचान और गतिविधियों की निगरानी आसान हो सकेगी।

केंद्र सरकार का मानना है कि समुद्र भारत की आर्थिक शक्ति का बड़ा आधार है, और उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग देश की “ब्लू इकोनॉमी” को नई गति देगा। इसी सोच के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने की नई नीति लागू की गई है, जो खास तौर पर छोटे मछुआरों और स्थानीय सहकारी समितियों को सशक्त बनाएगी।

इन नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब किसी भी विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज को भारतीय जलसीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इससे देश के स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा होगी, जो अब तक बड़े विदेशी जहाजों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते थे। सरकार ने साफ कहा है कि केवल भारतीय पंजीकृत नौकाओं को ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाएगी। इससे न केवल देश का मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

नई व्यवस्था में ‘मदर-चाइल्ड वेसल’ प्रणाली सबसे नवाचारपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत बड़ी नौकाएं (‘मदर वेसल’) समुद्र में मौजूद रहेंगी, जबकि छोटी नौकाएं (‘चाइल्ड वेसल’) तट से मछलियां पकड़कर वहीं बड़ी नौका को सौंप देंगी। इससे मछलियों को बार-बार तट पर लाने की जरूरत नहीं होगी और मछुआरों को अधिक समय तक समुद्र में रहकर उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों के मछुआरों को इससे बड़ा लाभ होगा।

सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन और समुद्री जीवों की सुरक्षा को भी नए नियमों का आधार बनाया है। एलईडी लाइट से मछली पकड़ने, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक तकनीकों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही, मछलियों की न्यूनतम कानूनी लंबाई तय की जाएगी ताकि प्रजनन योग्य छोटी मछलियां सुरक्षित रह सकें और समुद्री जैव विविधता पर असर न पड़े। अब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए ‘एक्सेस पास’ लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जो सरकार के ReALCRaft पोर्टल से निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध होगा। छोटे और पारंपरिक मछुआरों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। बड़े जहाजों में ट्रांसपोंडर उपकरण लगाना जरूरी होगा ताकि उनकी लोकेशन और गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख सकें। इसी क्रम में मछुआरों को क्यूआर कोड वाले आधार या फिशर आईडी कार्ड दिए जाएंगे, जिससे उनकी पहचान किसी भी समुद्री जांच या आपदा की स्थिति में तुरंत सत्यापित की जा सके। ReALCRaft पोर्टल को अब समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) से जोड़ा गया है। इससे मछली पकड़ने की अनुमति, गुणवत्ता जांच और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान होगी। इससे भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

नेपाल सीमा सील, तीन दिन तक ठप रहेगी आवाजाही: बिहार चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। संभावित अवैध गतिविधियों, नकदी, शराब या हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने और मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नौ नवंबर की सुबह से लेकर 11 नवंबर की शाम छह बजे तक सीमा पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया है। भारत-नेपाल के बीच लगभग 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो बिहार के आठ जिलों — पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज — से लगती है। इन सभी जिलों में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि सीमा पार से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। नेपाल से लगी सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। सीमा सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की विशेष तैनाती की गई है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दिन-रात गश्त चल रही है। अररिया जिले में तो विशेष रूप से 90 से अधिक नाकों पर एसएसबी जवानों को लगाया गया है, जहां हर वाहन और व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की तस्करी, नकदी या प्रतिबंधित सामान के आने-जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीमाई गांवों में निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को भी तैनात किया गया है।

मधुबनी जिले के जयनगर से जनकपुर (नेपाल) के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन सेवा को भी तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे (हाजीपुर मंडल) की ओर से नेपाल रेलवे प्रशासन को इस बारे में औपचारिक सूचना भेज दी गई है। जयनगर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक एस. एल. मीणा ने बताया कि नौ से 11 नवंबर तक यह ट्रेन सेवा बंद रहेगी और 12 नवंबर यानी बुधवार से फिर सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल सुरक्षा कारणों से उठाया गया है ताकि मतदान के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री सीमा पार से न आ सके।

अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में संयुक्त बलों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य मतदान के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी बाहरी प्रभाव या अवैध हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया को बचाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमाई इलाकों में रहने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और यदि किसी तरह की संदिग्ध हलचल दिखे तो तत्काल सूचना दें।

चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल अस्थायी है और मतदान समाप्त होने के बाद सीमा को सामान्य रूप से खोल दिया जाएगा। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच आवागमन, व्यापारिक गतिविधियाँ और रेल सेवा सामान्य रूप से बहाल हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, मतदान के बाद सीमा पर सभी चौकियों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी प्रकार की अशांति की संभावना न रहे। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं, जिनमें दूसरा चरण 11 नवंबर को निर्धारित है। इस चरण में सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ राज्य के कई अन्य जिलों में भी मतदान होना है। इन जिलों में सीमा पार से गतिविधियों पर सबसे अधिक निगरानी इसलिए रखी जा रही है क्योंकि अतीत में चुनावी अवधि के दौरान अवैध शराब और धन की आवाजाही के कई मामले सामने आए थे। प्रशासन को आशंका है कि सीमा की खुली प्रकृति का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सीमा पर तैनात जवानों को चौबीसों घंटे निगरानी में लगाया गया है और खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष और सीमा समन्वय केंद्र लगातार काम कर रहे हैं। नेपाल की ओर भी स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है ताकि दोनों देशों की ओर से मिलकर शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। इस प्रकार, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राज्य की सीमाओं पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। प्रशासन का दावा है कि हर मतदान केंद्र, सीमा चौकी और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त बल मौजूद है और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। बिहार सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 11 नवंबर का मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, तुर्किये ने 37 इजराइली अधिकारियों पर “जनसंहार” का आरोप लगाया

(जीएनएस)। इस्तांबुल। गाजा युद्ध को लेकर तुर्किये ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 37 वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस्तांबुल अभियोजन एजेंसी ने शुक्रवार को इन सभी के खिलाफ “जनसंहार” और “मानवता के विरुद्ध अपराध” के आरोप लगाए हैं। तुर्की अधिकारियों का कहना है कि यह कदम गाजा पट्टी में इजराइली हमलों के दौरान निर्दोष नागरिकों की मौत और मानवीय संस्थानों पर हमलों के मद्देनज़र उठाया गया है।

अभियोजन एजेंसी ने अपने आदेश में गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को “संगठित अपराध” की श्रेणी में बताया है। इसमें विशेष रूप से उस ‘तुर्किये-फिलिस्तीनी मित्रता अस्पताल’ पर हुए हमले का उल्लेख किया गया है, जिसे तुर्किये ने मानवीय सहायता के तौर पर गाजा में स्थापित किया था और जिसे हाल ही में इजराइली वायुसेना ने निशाना बनाया था।

वारंट में शामिल 37 अधिकारियों में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर समेत कई उच्चस्तरीय सैन्य और खुफिया अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, इस्तांबुल अभियोजन एजेंसी ने पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है।

तुर्किये की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साहसिक कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन पहले ही गाजा संघर्ष में फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन खुलकर जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में दायर उस याचिका का भी समर्थन किया था, जिसमें इजराइल पर “जनसंहार के आरोप” लगाए गए थे।

इस बीच, इजराइल ने तुर्की के कदम को पूरी तरह “राजनीतिक और निराधार” करार दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “एर्दोगन की सरकार न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरह वह तुर्की के विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाते हैं, अब उसी नीति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति किसी विदेशी अदालत के डर से नहीं बदलेगा।” गौरतलब है कि गाजा में फिलहाल युद्धविराम लागू है, जो अमेरिकी मध्यस्थता से 10 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। हालांकि, तुर्किये ने युद्धविराम के बावजूद इजराइल पर लगातार मानवीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और वह संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि तुर्किये का यह कदम मध्य-पूर्व की राजनीति में नए तनाव को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी नाटो सदस्य देश ने इजराइली प्रधानमंत्री और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

बीकॉम छात्र ने बीमारी और मानसिक तनाव से तंग आकर खुद को गोली से उड़ाया, गांव में मातम का माहौल

(जीएनएस)। गौतमबुद्ध नगर। बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला गांव में शुक्रवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक 20 वर्षीय बीकॉम छात्र ने अपने ही घर में देशी तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। मृतक की पहचान आकाश गिरी पुत्र प्रमोद गिरी के रूप में हुई है, जो बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे घर के अंदर अचानक गोली चलने की आवाज आई। परिवार के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा कि आकाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके सिर में गोली लगी थी। परिवार ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थाना बादलपुर के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने बताया कि छात्र ने अपने ही घर में देशी तमंचे से खुद को गोली मार ली थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना के समय घर में अन्य परिजन मौजूद थे, जो गोली चलने की आवाज सुनते ही कमरे में पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से तमंचा और एक खोखा बरामद किया है।

अमित भड़ाना ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। छात्र का मोबाइल फोन लॉक है, जिसे तकनीकी सहायता से खुलवाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि उसने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि आकाश कुछ समय से बीमार चल रहा था और लगातार मानसिक तनाव में था। डॉक्टरों ने उसे आराम की सलाह दी थी, लेकिन वह पढ़ाई और बीमारी के बीच परेशान रहता था।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि आकाश पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। कई बार वह खुद को कमरे में बंद कर लेता था और बात करना भी कम कर दिया था। माता-पिता ने उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा। पड़ोसियों के मुताबिक आकाश एक शांत और शालीन स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा पढ़ाई में ध्यान देता था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता था। गांव में उसकी मौत की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गई। हर कोई यही कह रहा था कि बीमारी और मानसिक तनाव ने एक होनहार युवा की जिंदगी छीन ली।

पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। इस बीच गांव में मातम पसरा हुआ है, हर कोई आकाश की असमय मृत्यु पर दुख व्यक्त कर रहा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है।यह घटना फिर एक बार इस सच्चाई को उजागर करती है कि आज के युवाओं में मानसिक तनाव और अवसाद किस कदर बढ़ चुका है। परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों को इस दिशा में संवेदनशील होकर युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है ताकि कोई और आकाश अपनी ही जिंदगी को खत्म करने जैसा कदम न उठाए।